सेवा शर्तों में छूट. नवनियुक्त 496 ग्रामीण विकास पदाधिकारी सीधे बने बीडीओ, ज्वाइन करते ही राजपत्रित का दर्जा

प्रभात खबर दिनांक - 13-08-14

प्रखंड स्तर पर निबटाएं समस्याएं : सीएम

कार्यालय व आवास के रखरखाव पर सालाना खर्च कर सकेंगे 10 लाख

संवाददाता, पटना

नवनियुक्त 496 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के पद पर पदस्थापित किया गया है. उनका पदस्थापन 15 अगस्त तक प्रखंडों में कर दिया जायेगा. इनकी सेवा शर्तों में तीन वर्षों की छूट दी गयी है. इन्हें राजपत्रित पदाधिकारी घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार ने हर बीडीओ को उनके प्रखंड कार्यालय के भवनों के रखरखाव व आवास के लिए सालाना 10 लाख रुपये खर्च करने की वित्तीय शक्ति दी है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारियों के उन्मुखी कार्यक्रम में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण विकास पदाधिकारी तीन वर्षों के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाते, उनकी सेवा शर्तों में तीन वर्षों की छूट दी गयी है. उनकी प्रोन्नति के भी व्यापक अवसर हैं. मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि ग्रामीण विकास की मूल प्रशासनिक तंत्र प्रखंड है और प्रखंडों के कार्यों की गुणवत्ता में कमी आयी है. उन्होंने नवनियुक्त बीडीओ को बताया कि पहले गिने-चुने लोग विधायक व सांसद से मिलते थे. अब दौर दूसरा आ गया है. अब अदना आदमी सीधे मुख्यमंत्री से मिल रहा है. इसके कारण समस्याओं की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है. जिस समस्या का समाधान प्रखंड या जिला स्तर पर हो जाना चाहिए, उसको लेकर लोग जनता दरबार में आ रहे हैं. जब सब काम मुख्यमंत्री व सचिवालय स्तर से होगा, तो फिर सिस्टम का क्या मतलब?

ग्राम शिविर लगाएं : पंचायती राज मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने नये पदाधिकारियों को पंचायत की नियमित ग्राम शिविरों के आयोजन कराने की सलाह दी. उन्हें कहा गया कि पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति व जिला पर्षद के सदस्यों से प्राप्त समस्याओं के निबटारे पर ध्यान देना होगा. प्रखंड स्तर पर जनता दरबार लगाना चाहिए. सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह ने पदाधिकारियों को स्थानीय भाषा को विकसित करने को कहा. साथ ही यह बताया कि उनके बेहतर कार्य से जनप्रतिनिधियों को सम्मान या अपमान मिल सकता है. कृषि विभाग के प्रधान सचिव सह मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी अमृत लाल मीणा ने कहा कि औसतन हर प्रखंड में 40 हजार परिवार होते हैं. इनमें 10 हजार परिवारों को प्रमाणपत्रों को लेकर प्रखंडों में जाना होता है. इसी तरह से 10 हजार ऐसे परिवार हैं, जो सरकार की योजनाओं पर निर्भर हैं. चाहे वह इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या अन्य योजनाएं हों. ऐसे परिवारों के साथ सहानुभूति के साथ काम होना चाहिए. बीडीओ को जनप्रतिनिधियों के साथ हर

हर माह होगी रैंकिंग

ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने नये बीडीओ को नसीहत दी कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निबटारा करेंगे, तो किसी को जिला या मुख्यमंत्री के पास नहीं आना पड़ेगा. ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा में पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है. इसी तरह से वे एक-एक बीडीओ के कार्यों की रैंकिंग प्रति माह करायेंगे. इसे जनता के बीच सार्वजनिक भी किया जायेगा. उन्होंने कहा कि अपने मिशन के प्रति अटूट आस्था रखनेवाले छोटे समूह को भी पहचान मिलती है. पहचान के लिए सौ साल की आवश्यकता नहीं. धैर्य और ईमानदारी से काम करें, तो कोई समस्या नहीं होगी.

नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारियों के उन्मुखी कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी.

आप खुश हैं, मगर मेरा दिल दुखी

पटना. मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में अब भी समस्याएं हैं. वहां जाने पर बहुत निराशा होती है. मुख्यमंत्री के रूप में दो बार गांव जाने का मौका मिला. वहां हजारों नर-नारियों ने स्वागत किया. यह देख मेरे साथ गये अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि आपको देख कर जनता में गजब उत्साह है. लेकिन, मैंने कहा कि आप खुश हैं, पर मेरा दिल दुःखी है. लोग फटे कपड़े पहने हुए हैं. उनका घर टूटा हुआ है. मुरगी व सूअर खाते हैं. क्या यही जीवन है? देश की आजादी के 67 वर्षों के बाद भी हमने क्या काम किया. अर्थशास्त्री आंकड़ों पर आधारित बात करते हैं, पर व्यावहारिक पहलू यह भी है. सरकारी सिस्टम के फेल होने पर लोग दूसरा रास्ता (नक्सली) अख्तियार करते हैं. उन्हें कोई बंदूक थमा देता है. उन्होंने कहा कि प्रखंडों में सिंगल विंडो सिस्टम अपनाएं. ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया वर्ग पैदा हो गया है. वह है बिचौलियों का. बैंक हो या थाना, सभी जगह बिचौलिये आ गये हैं. इसे मिटा देने पर 70 फीसदी समस्याओं का हल हो जायेगा.